here says that all agreements registered will be regarded as prejudicial unless the Commission comes to a positive finding that they are necessary and they will not raise prices etc. That is automatically they would become bad unless the Commission gives a positive finding in their favour. This is putting it negatively.

SHRI F. A. AHMED: The presumption is that all agreements which tend to bring about restriction of trade are bad unless reasons are given on account of which the Commission comes to a finding that they are not prejudicial to public interest.

SHRI HIMATSINGKA: There is another provision whereby all agreements registered, whether bad or not, will all be regarded as bad unless there is a positive finding by the Commission.

SHRI F. A. AHMED: We would not allow agreements registered which stand in the way of the operation of this Bill. They have been brought within the purview of the Bill. We do not want to leave a loophole thereby excluding agreements entered into which are detrimental to public interest.

The original provision in the original Bill actually provided the circumstances in which a trade practice would be deemed to be prejudicial to the public interest. The question as to whether such practice was in existence was left to be determined by the Commission. But the Joint Committee felt that instead of leaving the matter to them, it should be specified on the basis of which the Commission can come to a finding whether it is prejudicial to public interest.

SHRI HIMATSINGKA: Automatically it will be regarded as bad unless there is a positive finding.

SHRI F. A. AHMED: Here an improvement has been made. Some indications have been given that for these reasons at least they cannot be regarded as prejudicial to public interest. This is an improvement over the original Bill which the Committee made to meet the objection.

As I pointed out earlier, our objective is not to restrict economic or industrial development, but to check such tendencies as are against our socio-economic objectives which we have accepted and for which the country is anxious. I am very glad that an overwhelming number of Members of this House have given support to these concepts and objectives and I, therefore, commend my motion for the acceptance of this House.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.50 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) ORDINANCE AND FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) BILL

MR. DEPUTY SPEAKER: The Bill and the Resolution are to be taken up together. The time allotted is three hours.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I beg to move:

"This House disapproves of the Foreign Exchange Regulation (Amendment) Ordinance, 1969 (Ordinance No. 9 of 1969) promulgated by the President on the 13th November 1969".

उपाध्यक्ष महोदय अपने डिस्प्रूवल के प्रस्ताव को पेश करते हुए मैं आर्डिनेन्स की स्पिरिट का तो स्वागत करता हुं क्योंकि मैं इस के विरूद्ध नहीं हुं और मैं समझता हूं कि आज अन्डर-इनवार्यसिग और ओवर-इन्वार्यसिग तथा फारेन एक्स्चेंज को बचाने की जो बीमारी हमारे देश में चली है उसको रोकने के लिए यह आर्डिनेन्स लाया गया है । लेकिन मुझ को इस पर दो ऐतराज हैं । एक ऐतराज तो इस बात पर है कि यह आर्डिनेन्स 13 नवम्बर को इशू किया गया था जब कि पार्लियामेंट 17 तारीख को शुरू होने वाली थी

[श्री कंवर लाल गुप्त]

मेरा कहना यह है कि यह सरकार के लिए ठीक नहीं है कि जब पार्लियामेन्ट मिलने वाली हो तब किसी प्रकार का ग्रार्डिनेन्स हफ्ते या दो हफ्ते पहले निकाला जाय — यह डेमोक्रेटिक ट्रेडिसन्स के खिलाफ है। दूसरा ऐतराज यह है कि जो विधेयक सरकार लाई है वह इन्कम्प्लीट है, वह ग्रपनी जगह पर कम्प्लीट नहीं है।

ग्रन्डर इन्वायसिंग ग्रौर ग्रोवर-इन्वायसिंग की जो समस्या है वह इतनी काम्प्लिकेटेड है जिस का ठिकाना नहीं है। मुझे ग्राशा थी कि सरकार इस के लिए एक काम्प्रिहेन्सिव बिल लायेगी जो ज्यादा एफेक्टिव होगा ग्रौर उस में जितने भी लूप होल्स है उन को रोकेगा। उन को रोक कर जो डिफाल्टर्स हैं उन को सख्त सजा दी जायेगी। लेकिन मुझे दुख है कि उस के बजाय सरकार यह पीसमील लेजीस्लेशन लाई है। यह भी एक वजह है जिस के कारण मैं इस का विरोध करता हूं।

ग्रभी हमारे देश में जो फोरेन एक्स्चेन्ज की दिक्कत है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है ग्रौर उस दिक्कत के लिए मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पालिटीशियन्स हैं, जो बड़े बड़े, ग्रफसर हैं ग्रौर जो करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं यह तीनों मिल कर साजिस करते हैं जिस के कारण देश का करोड़ों रुपये का फारेन एक्स्चेन्ज हर साल बरबाद होता है ग्राप को मालूम होगा कि एक केस नयनमल पूनशी शाह का है, जिस के बारे में कहा जाता है कि पुलिस ने उस के यहां रेड भी की। वह सिल्वर स्मग्लिंग का काम करता था। वह पकड़ा भी गया लेकिन ग्राप को ताज्जुब होगा कि चूंकि उस की मित्रता राजस्थान के चीफ मिनिस्टर श्री सुखाडिया से थी ग्रौर चूंकि उन्होंने कुछ पैसा राजस्थान को दे दिया, इस लिये इस केस को दबा दिया गया।

17.55 hrs.

[SHRI M. S. RANA *in the Chair*]

ग्रौर ग्रधिक उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी तरह से नई दिल्ली में एक प्रिंटर्स हाउस है उस के बारे में भी यही हुग्रा है। ग्रौर तो ग्रौर ग्राप को सुन कर ग्राश्चर्य होगा कि ग्रौर जो महेश योगी हैं उन का भी विदेशों मे बहुत सा ग्रकाउंट है लेकिन इस के बारे में भी सरकार ने कोई कार्रवाही नहीं की। उन का करोड़ों रुपया विदेशक बैंकों में है। सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिस से वह मालूम कर सके कि विदेशी बैंकों में किस-किस का कितना-कितना रुपया जमा है ग्रौर लोंगो को बाध्य कर सकें कि वह ग्रपना रुपया वहां से निकाल कर यहां लायें इस के बारे में सरकार को पूरी जानकारी भी नहीं है। सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी है। मेरा ग्रनुमान है कि इस प्रकार से सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपयों का घाटा होता है जो ग्रन्डर इन्वायसिंग ग्रौर ग्रोवर-इन्वायसिंग के जरिये से होता है। बैक-डोर मेथड्स ग्रौर करप्ट प्रेक्टिसेज़ से भी उस को काफी घाटा होता है। कनाट प्लेस में खुले ग्राम फारेन एक्स-चेन्ज मिलता है, चाहे जितना ग्राप ले लीजिए। उस में कोई दिक्कत नहीं होती। यह एक कंट्रीवाइड रैकट है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि यह एक इंटर-नैशनल रैकट है जिस को दूर करने में सरकार नाकामयाब हुई है क्योंकि इस में छोटे लोग शामिल नहीं है, उस में बड़े-बड़े इन्फ्लुएन्शल लोग शामिल हैं। एक केस मैं बतलाना चाहता हूं ग्रौर मैं चाहुंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस की इन्क्वायरी करें। एक तो मैंने महेश योगी का केस बतलाया, दूसरे कोई डेढ़ साल पहले एक मि० बाचा विदेश से यहां ग्राये। उन की धर्म पत्नी भी उन के साथ थीं। लाखों रुपये की करेन्सी यहां लाये, ग्रौर जब वह पकड़े गये तो गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया के एक डिप्टी सेक्रेट्री उन को रिसीव करने के लिये ग्राये ग्रौर जब कस्टम वालों ने उन से पूछा कि ग्राप इतनी करेंसी ग्रौर एक्स्चेन्ज क्यों लाये तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस को बड़े बड़े ग्रफसरों के लिये लाया हूं। उन का यह स्टेटमेंट रिकार्ड है ग्रौर ग्राज भी उन की फाइल में है। उन को जमानत पर छोड़ दिया गया क्योंकि एक डिप्टी सेक्रेट्री ने उन को बचाया था। वह भी इन्फ्लुएन्शल ग्रादमी थे जिन्होंने

उन को बचाया था। उन का यह स्टेटमेंट रिकार्ड पर है कि वह बड़े-बड़े अफसरों के लिए लाये हैं। तब भी उन की करेंसी वापस कर दी गई और उन को छोड़ भी दिया गया। सिर्फ थोड़ा जुर्माना करके उन का सारा सामान वापस कर दिया गया। यह एक घटना नहीं है, इस तरह की अनेक घटनाएं बतलाई जा सकती हैं। क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा केस वतलायेंगे कि जितने लोगों ने फारेन एक्स्चेन्ज रुल्स का वायोलेशन किया है, उन में से कितने केसेज में उन का फारेन एक्स्चेन्ज पूरा कांफिस्केट किया गया है? शायद ही कोई ऐसा केस हो जिस में पूरे का पूरा फारेन एक्स्चेन्ज कांफिस्केट किया गया हो। मेरे ख्याल से तो एक भी नहीं है।

मैं यहां यह मांग करना चहाता हूं कि सरकार एक हाई पावर कमीशन विठलाये जो फारेन एक्स्चेन्ज कंट्रोल की वर्किंग के बारे में जांच करे और देखे कि हमारे देश में आज जो फारेन एक्स्चेन्ज कंट्रोल है वह किस तरह से काम कर रही है। अभी तक सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई भी एन्क्वायरी नहीं की। न तो किसी इंडस्ट्री के वारे में एन्क्वायरी की है न किसी और के बारे में की है। उस ने बहुत सी बातों की एन्क्वायरी की है, लेकिन यह फारेन एक्स्चेन्ज की समस्या देश के सामने सव से वड़ी और काम्प्लिकेटेड समस्या है, इस को सरकार जितनी लाइट-हार्टेडली और शैवीली ट्रीट कर रही है उतनी किसी दूसरी समस्या को नहीं कर रही है। मेरी पहली मांग यह है कि सरकार को एक हाई पावर कमीशन जल्दी से जल्दी विठलाना चाहिए जो हमारे फारेन एक्स्चेन्ज की सारी वर्किंग को, कि वह कैसे चल रहा है और उस में क्या खामियां हैं, उन को देखे और वतलाये कि वह खामियां कैसे दूर हो सकती हैं और कौन सी अच्छी वातें हमारे देश में आ सकती हैं।

18 hrs.

मैं दूसरा एक सुझाव देना चाहता हूं। जो वड़ी-वड़ी फर्मे या व्यक्ति फारेन एक्स्चेन्ज का वायोलेशन करें, उनके नाम और पते सरकार को अखवारों और गजेट में छापने चाहिएं। इनकम टैक्स का जो वायोलेशन करते हैं उनके तो छपते हैं लेकिन फारेन एक्स्चेन्ज का जो वायोलेशन करते हैं, उनके नहीं छपते हैं। अगर उनके नाम छपेंगे ती उसका जो इफेक्ट होगा वह डिटरेंट होगा। साथ ही उनके जो लाइसेंसिस है, जो उनको सरकार द्वारा जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, या उनको जो परमिटस मिले हुए हैं वे भी खत्म कर दिये जाने चाहिएं। लोगों को मालूम होना चाहिए कि वे डिफाल्टर्स हैं और इन्होंने फारेन एक्स्चेन्ज का वायोलेशन किया है। रुल्ज़ में शायद यह चीज़ प्रोवाइडिड है लेकिन प्रोविज़न होने के बाद भी सरकार ने आज तक किसी का नाम या पते गजेट में या समाचार पत्रों में छापे नहीं है। इस वास्ते फारेन एक्स्चेन्ज का वायोलेशन करने वालों के नाम और पते छपने चाहिएं।

कोई डिवाइस या तरीका क्या आपके पास ऐसा है जिससे फारेन एक्स्चेन्ज का आप रिपैट्रियेशन कर सकते हैं? मेरे ख्याल में अभी तक हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है। इसी कारण से बाहर से जो फारेन एक्स्चेन्ज का रिपैट्रियशन होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। सरकार इस तरह का कोई मैथड बनाये जिससे हमारा बाहर जो रुपया जमा है, बैंकों में लोगों का जमा है और वगैर परमिशन के उन्होंने एकांउट खोले हुए हैं, वह रुपया आप यहां मंगवा सकें। अभी सरकार इन बातों के बारे में बहुत लीनिएंट व्यू लेती रहीं है। जो इस तरह का वायोलेशन करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाही होनी चाहिए। मैंने एक सवाल पूछा था कि कौन-कौन से लोग हैं जिन्होंने इस तरह से वायोलेशन किया है। उसके जबाव में मुझे एक लम्बी लिस्ट दे दी गई। उनकी फारेन एक्स्चेन्ज की वायोलेशन काफी वड़ी है लेकिन किसी को पांच सौ रुपये और किसी को दो हजार जुर्माना हुआ। एक भी केस ऐसा नहीं है जिस में सरकार ने सारे का सारा फारेन एक्स्चेन्ज जब्त कर लिया हो। पांच दस हजार रुपया जुर्माना कर देने से काम

[श्री कंवर लाल गुप्त]

नहीं चलेगा। जो सीरियस वायोलेशन करता है उसको फिजिकल सजा भी होनी चाहिए, कैद की भी सजा होनी चाहिए।

आर्डिनेंस का तो मैं समर्थन करता हूं। इसका कारण यह है जो माल बाहर जाता है उसको चैक करने के लिए सरकार रोक लेती थी और यह जो पावर थी इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में खत्म कर दिया था। आर्डिनेंस जो आप ने पास किया, उसकी जो भावना है, उसकी तो मैं कद्र करता हूं लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह एक कम्प्रिहेंसिव बिल लाये और उसको लाने से पहले एक इनक्वायरी कमिशन बिठाये। यह कमीशन फारेन एक्स्चेन्ज के वर्किंग के बारे में और उसके कंट्रोल के बारे में जांच करे। उसकी जो रिपोर्ट आए उसके आधार पर सरकार एक कम्प्रिहेंसिव बिल लाये। इस बीच में मैं चाहता हूं कि जिन-जिन लोगों ने वायोलेशन की है, उनके नाम और पते गजेट में छापे जायें।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): Sir, the purpose of this Bill which I have brought before the House is very much limited. As far as the Foreign Exchange Act, 1947, is concerned, we are now coming forward for an amendment of section 12(1) of this Act. I agree with the hon. Member, Shri Kanwar Lal Gupta, that the ordinance was promulgated on the eve of the sitting of Parliament; the Parliament was to meet on the 17th November, and the ordinance was brought on the 13th. Previously, according to the old section 12(1), any restriction imposed by it was deemed to have been imposed under section 11 of the Customs Act of 1962, and it conferred powers to the customs officers to detain the goods intended for export when the full export value has not been correctly stated in the declaration. This position was obtaining, in respect of the customs officers or authorities right from the time when the Act came into force. This was sustained by various high court decisions and rulings, and according to those high court decisions and rulings, it was found that this section, section 12(1), empowered the customs authorities to detain the goods provided the declaration in this particular form was not correctly given. The declaration was to be given in form GRP/EP according to the rule framed in pursuance of section 27 of the Foreign Exchange Regulation Act. This matter went to the Supreme Court, and the Supreme Court was pleased to observe that as far as section 12(1) was concerned, the requirement of this section is limited to the purpose that the party should give a declaration and there should be a proper time and procedure for the payment of the foreign exchange received for the export of these goods. The Supreme Court was further pleased to observe that as far as this particular section was concerned, it did not give the authority to the customs people to detain the goods and it was open for the customs authorities to proceed against the parties concerned under section 23A. Therefore, to that extent, the customs authorities were handicapped. This particular decision of the Supreme Court came in September. I certainly agree that to the extent that we wanted to bring forth this change, this should have been done a little earlier, and the time-lag was there; we could not bring forth this particular measure a little earlier, which we really wanted to do.

But, at the same time, time was passing, and it was considered desirable that in order to check the most valuable foreign exchange evasion in the form of over-invoicing and under-invoicing, it was necessary to detain the goods rather than allow the goods to pass and then take action against the concerned party under section 23A and proceed in the court of law according to the provisions of the law, when the customs authorities could very well detain the goods without proper declaration; then this was the proper course and therefore the Government thought it fit and desirable to bring forth this ordinance. Therefore, the ordinance was brought forward and the Bill is before the hon. House.

In the course of his opening speech, Shri Kanwar Lal Gupta has brought forward very many points and cases

before the hon. House. As far as these particular cases are concerned, I never expected that he would be raising such individual cases in the course of his opening remarks, but certainly, about whatever cases he has mentioned during the course of his speech, I shall try to reply when we take up the Bill tomorrow, sometime, and I shall put forth the facts, whatever are available with me, so that the House will be able to know as to how we are proceeding in these matters.

With regard to the other point, that instead of bringing this piecemeal legislation the Government should have brought forward a comprehensive legislation because the most valuable thing, that is, the foreign exchange is being lost, and there are cases of over-invoicing and under-invoicing, and besides this, there are foreign exchange rackets and there is smuggling and all this is going on a considerable scale as put forth by the hon. Member, I wish to say this.

It is true that foreign exchange violations are taking place. It is also true that there are cases of over-invoicing and under-invoicing. That is why the Government has already decided, considering all these aspects of the question, that there should be a comprehensive Bill, that the entire matter should be reviewed in the light of present happenings and we should see how to tighten the law, the procedure as well as the administrative machinery. From that point of view a comprehensive Bill will certainly come before the House but at the moment our concern was, in the light of the Supreme Court's decision, to amend this clause to the extent that the Customs authorities could retain the power which they were exercising up till now for the detention of these goods if the invoice value or the full export value of the goods declared was not the same as that contracted with the buyer, if it was not a fair valuation of the proceeds of goods which are unsold. The proceeds resulting from the sale of goods will be delivered to the authorised bank. All these changes are being made through the Bill before the House.

As far as the Bill is concerned, it is a small Bill with four clauses, one or two of which are only enabling clauses. The main clause is clause 2 which is being brought for the change of section 12(1).

SHRI KANWAR LAL GUPTA: What about a high-power commission to review the working of the foreign exchange control and publishing the names of defaulters?

SHRI P. C. SETHI: These are suggestions for action. I have said that Government is considering bringing forward a comprehensive Bill for this purpose. When we bring forward that comprehensive legislation, we would not only go into the ailments which exist today but we would certainly have expert opinion and advice before bringing forward that comprehensive legislation. It is there without saying that to that extent we would certainly be guided by the expert advice and the various suggestions which are before us. This is a very important measure and we would not bring forward that measure in a piecemeal or haphazard manner. We would go into all the aspects of foreign exchange violations, over-invoicing and under-invoicing and then come before the House with a good measure.

Apart from that, there are other points which the hon. Member has raised, particularly of people getting away with small penalties imposed against them for foreign exchange violations. When we bring forward the comprehensive legislation, we would also certainly have to take into account the various penalties that are to be imposed for violations of foreign exchange regulations.

SHRI HIMATSINGKA (Godda): The penalties are there.

SHRI P. C. SETHI: Whether those penalties are properly inflicted, whether they are completely and fully deterrent or not—all these aspects will have to be gone into. At this stage, therefore, I have nothing more to add.

With regard to the various points raised about particular parties, I would come before the House later but just now I would like to refute

[Shri P. C. Sethi]
one particular allegation which the hon. Member was pleased to make against the Chief Minister of Rajasthan, namely, that Nainmull Poojanji is not being proceeded against properly by the Department because he gave certain sums of money to the Chief Minister of Rajasthan. That is not correct. Nainmull Poojanji is being prosecuted. Some of the persons are already under custody; they have not been released. The party had gone from the Presidency Court to the High Court and from the High Court to the Supreme Court but the Supreme Court has upheld the Government side and has not allowed to release of those persons. They are being proceeded against. It is not correct that the Government is not taking suitable and proper legal action against this party.

Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Foreign Exchange Regulation Act, 1947, be taken into consideration".

MR. CHAIRMAN: The Statutory Resolution and the Motion regarding the Bill are before the House.

There is an amendment for circulation in the name of Shri Yashpal Singh. He is not here.

SHRI HIMATSINGKA: Mr. Chairman, so far as the intention behind the Bill is concerned, I feel that the Government were justified in promulgating the Ordinance in view of the decision of the Supreme Court which struck down the practice which was being followed for so long by the Department. It was only fit and proper that this action should have been taken much earlier—the judgment was delivered some time in September—then this valuable time would not have been lost. Instead of waiting for so long, action ought to have been taken much earlier.

A very large amount of foreign exchange is being lost on account of proper action not being taken by Government in various respects. You go to any market where various articles are being sold and you will find that they are full of foreign commodities, commodities made and manufactured in other countries whose import is banned and is not being permitted. You can get any number of such articles in any shop that you enter. Go to New Market in Calcutta or to any of the shops in Delhi or Bombay and you will find that they are stuffed with articles whose import is banned. Still, you can get them; perhaps you may have to give them your requirements and after a few minutes you get them. How is it possible for these businessmen or shopkeepers to sell these things openly if proper steps and action are taken to check these things? If you go to any market, you will find that it is flooded with Chinese fountain pens. How are they coming unless we are negligent in preventing their coming? Fountain pens, blades, suitlength pieces, transistors, gold—all these things are coming.

We hear every time that so much gold has been seized. We do not know how many consignments of such gold escaped seizure. As a matter of fact, ten times they escape seizure and perhaps once it is seized. Therefore a very large amount of valuable exchange is being lost and I feel that very drastic and regular action should be taken by the Customs authorities to arrange raids in almost all these markets where foreign articles are being exhibited and sold day in and day out without any check or hindrance or any kind of difficulty. Unless such steps are taken, you can never prevent smuggling and loss of foreign exchange.

Merely bringing forward legislation is not sufficient. The legislation is there. Even now they can stop all these things provided proper steps are taken.

So far as the penalty provisions are concerned, as far as I remember, the power of the Customs authorities is very, very wide. They can impose penalties to a very large extent, perhaps three or four times the total value of the goods. I do not remember exactly the amount but certainly it is more than three times the value of the goods. They can also seize the goods and forfeit them and take other steps. Therefore the power is there but the power has to be utilised in a proper manner to prevent the various

leakages that are taking place in foreign exchange. If that is done a very large amount of foreign exchange can be saved to the country and our balances will very much improve.

Along with the legislative measure that is intended to be brought forward, other steps are absolutely necessary. If those steps are not taken, any amount of legislation may be brought forward but it will not be effective. Very big articles like taperecorders costing Rs. 1,000 or so you can get in the market, any number of them. If steps are taken, it can be checked. Therefore I invite the attention of the hon. Minister to the practical side of the loss which is being incurred and request him to take some steps to prevent that.

With these remarks, I support the Bill.

SHRI K. M. ABRAHAM (Kottayam): Mr. Chairman, Sir, what is the purpose of this Bill? It seeks to prohibit the export of goods whose declared value is in the customs authority below the normally realisable value.

The practice of under-invoicing of exports and over-invoicing of imports has been going on in this country ever since the Foreign Exchange Regulation has been enforced.

Whatever else may be said about our traders, it cannot be said that they are honest to the country. It is a well-known fact that there is a mounting level of smuggled gold and other luxury goods into our land because of the financing by surplus foreign exchange earned by these traders outside. Probably the activities of these smugglers have reached such a tremendous proportion as to endanger the economic stability of the country.

It is by withholding or denying the due credit of foreign exchange which we should otherwise get. These transactions lead to the weakening of the position of the Indian currency abroad and to the depreciation of its exchange value in relation to other foreign currencies. This is criminal, antinational and unpatriotic act and the traders who are caught in this game should be treated as traitors. There should be no mercy shown to them.

We know for example that in recent years some of the export items have been fetching far less foreign exchange to the country than we should otherwise be getting. It has been pointed out that some of the foreign companies who export tea have been grossly under-invoicing tea exports. Similarly, a number of light engineering items like sewing machines, cycle spare parts, etc. are known to have been exported at much below their value in foreign countries.

We know the case of M/s Jadin Henderson & Co. who have cheated this country of crores of rupees worth of foreign exchange in their import and export operations. It was also noted by a committee which examined the foreign collaboration agreements 'that a large number of foreign collaborators have been indulging in over-invoicing of imports'. The study cites many instances in support of its findings about the supply of second quality machinery at high costs. "In one case it was for lift trucks imported at Rs. 60,000 a piece while the local one ton pedal lifts are selling for less than Rs. 15,000. In a factory manufacturing electrical measuring instruments, with foreign collaboration, it is seen that six out of ten imported drilling machines were idle, because they were not required at any stage of operation".

There are hundreds of such instances in which the foreign collaborators have been misusing the terms of agreements. Firstly they import raw materials at very high cost even though identical substitutes are available locally at reasonable price. Secondly, they import unnecessary and secondhand or sub-standard machinery and equipment at prohibitive costs. Thirdly, they palm off large number of items which are of no service to the nation.

It would thus be clear that this country has been losing vast amount of foreign exchange by the trickery and unscrupulousness of the traders and manufactureres, both foreign and Indian. The foreign exchange regulations as they have operated in this

[Shri K. M. Abraham]

country, have only harassed honest and small businessmen whereas the big sharks and foreign collaborators and monopolists have got away with large scale loot of the country. In our opinion, the only solution to this problem is to take over the entire foreign trade of the State. Only that can save our country and its resources from the predatory greed of foreign monopolists and Indian blackmarketeers.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुवनी): सभापति जी, मोटे तौर पर विधेयक का समर्थन ही में करता हूं कि विदेशी मुद्रा विनिमय जो है इस की वचत होनी चाहिए। यह जो सरकार को मुद्रा नहीं मिल पाती है यह मिलनी चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था को हमें आगे बढ़ना है और विकास करना है। लेकिन सरकारी आंकड़े और सरकारी रपटें बताती हैं, तिवारी कमेटी की रपट बताती है कि भारत सरकार को 100 करोड़ रुपये का घाटा लगता है स्मगलिंग के जरिये या दूसरे जरिये से जो कि कस्टम अधिकारी पकड़ नहीं पाते हैं और विदेशी मुद्रा मिल नहीं पाती हैं। यह दुःख की बात है। इस को सख्ती के साथ रोकना चाहिए जितनी सख्ती हो सके उतनी सख्ती के साथ, लेकिन इस को हम तभी रोक सकते हैं जबकि पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने पर वार फुटिंग पर काम करने के लिए एक अच्छी मशीनरी हम इस के लिए बनाएं। यह जो आप ने विधेयक में पावर दी है कस्टम्स अधिकारी को यदि कोई डिक्लेरेशन नहीं करता है तो डिक्लेशन न करने के खिलाफ ही ऐक्शन नहीं लीजिए बल्कि माल को भी ज़ब्त कर लीजिए, यह ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गारंटी है कि कस्टम अधिकारी धांधली नहीं करेगा, वह वार फुटिंग पर काम करेगा, मुस्तैदी से इस की क्या गारंटी है, इसके लिए क्या रास्ता, क्या आउटलेट है ? इस बीमारी को कौन रोकेगा ? तो आप मशीनरी जो बनाते हैं वह बनाएं लेकिन उस मशीनरी पर हिन्दुस्तान के पैमाने पर ठीक से वार फुटिंग पर चलाने के लिए भी आप को सोचना होगा। इस के साथ ही एक उस के मातहत हिन्दुस्तान और नेपाल के बार्डर और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के वोर्डर के लिए एक खास मशीनरी आप बनायें, कोई खास व्यवस्था आप करें। ज्यादा स्मगलिंग और फारेन एक्स्चेन्ज जिससे मिलना चाहिए वह जो नहीं मिलता, उस में ज्यादा जो घाटा लगता है वह मैं समझता हूं कि भारत नेपाल और पाकिस्तान के वोर्डर पर ज्यादा होता है। अभी हाल ही में कुछ तीर्थयात्री अफगानिस्तान से आये और हुसैनीवाला में उन के साथ बहुत सा माल था। मैंने सवाल भी किया था, काल अटेशंन भी दिया था वह शायद वह उन्होंने मंजूर नहीं किया, माननीय मंत्री जी वतायेंगे कि कितने का माल पकड़ा गया और कितना फारेन एक्स्चेन्ज का माल उन के साथ था ? तो इस तरह से हिन्दुस्तान पांकिस्तान और हिन्दुस्तान नेपाल के बोर्डर से बहुत स्मगलिंग होता है जिस से हिन्दुस्तान को घाटा आता है। इस चीज़ को सख्ती से रोकना चाहिए। लेकिन जब हम चाहते हैं कि फारेन एक्सचेन्ज का घाटा हम को न लगे, विदेशी मुद्रा हमें मिले, इस के लिए कुछ सख्ती करते हैं तो इस का मतलव यह नहीं है दूसरे मामलों में जहां हम को लिवरलाइजेशन करना चाहिए वहां हम लिवरलाइजेशन न करें। जैसे विद्यार्थी जो पढ़ने जाते हैं उनको जो जायज फारेन एक्सचेन्ज की रिक्वायरमेंट है उसको क्यों नहीं लिवरल रूप में देते हैं। बहुत से तो मेरे पास आते रहते हैं, कितनी दौड़ धूप उसमें करनी पड़ती है, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली कई जगह पैरवी करते हैं तब जाकर कहीं फारेन एक्सचेन्ज रिलीज़ करते हैं। सख्ती का मतलव यह नहीं है कि आंख बन्द करके आप के अफसरान काम करें। वह आंख खोल कर काम करें। वहां लिवरलाइजेशन की जरूरत है, वहां सख्ती की जरूरत नहीं है। ऐसे भी उदाहरण ह जहां विद्यार्थी फारेन एक्सचेन्ज बचाते हैं। यहां से कोटा ले जाते हैं, लेकिन आप का फारेन एक्सचेन्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपना खर्च वहां काम करके निकालत हैं और आप का पैसा लेते नहीं है। आप के एक्सचेन्ज पर कोई धक्का नहीं लगता

है। इन सब बातों को आप को सोचना होगा। लेकिन इस विधेयक में, सभापति महोदय जो बातें हैं कि जो ओफेंन्स करेगा उसको व सज़ा देंगे, इससे ही काम नहीं चलेगा। जो रिपोर्ट करता है, दो तीन दफ़ा रिपोर्ट करता है, उस पर जुर्माना हो, यह काफी नहीं है, उस का बाकायदा लाइसेंस जब्त होना चाहिए, उस को आगे एक्सपोर्ट की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए। जो हैबीचुअल ओफेंन्डर है, उस का तो आगे के लिए रास्ता ही बन्द कर देना चाहिए। यदि सरकार मजबती के साथ काम करेगी, आंख खोल कर काम करेगी तो मैं समझता हूं कि जो 100 करोड़ रुपया का घाटा आपको हर साल लगता है, वह कम हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ मोटे तौर पर मैं इस का समर्थन करता हूं।

18.32 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, December 19, 1969, *Agrahayana* 28, 1891 (*Saka*).